1. नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI)।

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सचिव) और अध्यक्ष NIXI ने आज भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI) के लिए तीन पथ तोड़ने वाली पहलों का उद्घाटन किया। इस लॉन्च के साथ, NIXI ने DOT & MeitY के साथ देश में IPv6 जागरूकता और गोद लेने के लिए एक सहायक भूमिका निभाने की घोषणा की है।
- IPv6 विशेषज्ञ पैनल (आईपी गुरु) (https://nixi.in):
- आईपी गुरु उन सभी भारतीय संस्थाओं को समर्थन देने के लिए एक समूह है जो आईपीवी 6 को स्थानांतरित करने और अपनाने के लिए तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त IPv6 विशेषज्ञ समूह एजेंसी को पहचानने और काम पर रखने में मदद करेगा जो IPv6 को अपनाने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करके ग्राहक को समाप्त करने में मदद करेगा। यह पैनल ऐसी सभी भारतीय संस्थाओं का मार्गदर्शन करेगा और IPv6 को अपनाने में मदद करेगा। यह IPv6 को बढ़ावा देने के लिए डॉट, मीटीवाई और समुदाय का एक संयुक्त प्रयास है। विशेषज्ञ पैनल समूह में सरकारी और निजी संगठनों के सदस्य शामिल हैं।
- NIXI अकादमी (https://training.nixi.in):
- NIXI अकादमी भारत में तकनीकी / गैर-तकनीकी लोगों को शिक्षित करने और IPv6 जैसी प्रौद्योगिकियों को फिर से तैयार करने के लिए बनाई गई है जो आमतौर पर शैक्षिक संस्थानों में नहीं सिखाई जाती हैं। उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म नेटवर्क ऑपरेटरों और शिक्षकों को सर्वोत्तम प्रथाओं, सिद्धांतों और तकनीकों को समझने में मदद करता है; बेहतर इंटरनेट संसाधनों का प्रबंधन; और अधिक प्रभावी ढंग से उपयुक्त इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करें। NIXI अकादमी में एक आईपीवी 6 प्रशिक्षण पोर्टल शामिल है जो समुदाय को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से विकसित किया गया है। इस अकादमी के माध्यम से हमारा इंटरनेट समुदाय विभिन्न तकनीकी मॉड्यूल से सीखने में सक्षम होगा। सफल उम्मीदवार (परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद) NIXI से प्रमाण पत्र ले सकते हैं, जो उद्योग में नौकरी खोजने / अपग्रेड करने के लिए उपयोगी होगा।
- NIXI-IP-INDEX (https://ipv6.nixi.in) :
- NIXI ने इंटरनेट समुदाय के लिए एक IPv6 इंडेक्स पोर्टल विकसित किया है। NIXI-IP-INDEX पोर्टल भारत और दुनिया भर में IPv6 गोद लेने की दर का प्रदर्शन करेगा। इसका उपयोग दुनिया में अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ IPv6 भारतीय गोद लेने की दर की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। NIXI आने वाले दिनों में इस पोर्टल को IPv6, IPv6 ट्रैफिक आदि में वेब को अपनाने के साथ आबाद करेगा। यह पोर्टल संगठनों को आईपीवी 6 को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, तकनीकी संगठनों द्वारा योजना के लिए इनपुट प्रदान करेगा और शिक्षाविदों द्वारा शोध करेगा।
- NIXI के बारे में
- भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI) एक गैर-लाभकारी संगठन है (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) 2003 के बाद से भारत के नागरिकों को निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को फैलाने के लिए काम कर रहा है:
    - इंटरनेट एक्सचेंज, जिनके माध्यम से इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान आईएसपी, डेटा सेंटर और सीडीएन के बीच किया जाता है।
    - .IN देश के लिए .IN देश कोड डोमेन और .grat IDN डोमेन के प्रबंधन, संचालन और संचालन।
    - IRINN, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IPv4 / IPv6) का प्रबंधन और संचालन।

2. राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद

- रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) की पहली बैठक की अध्यक्षता की।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग (DPIIT) ने देश में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया था।
- पदेन सदस्यों के अलावा, परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या होती है, जो सफल स्टार्टअप के संस्थापकों, भारत में बढ़ी हुई और बढ़ी हुई कंपनियों के संस्थापकों, स्टार्टअप्स में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्तियों जैसे विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं। इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर के हितों का प्रतिनिधित्व करना, स्टार्टअप्स के हितधारकों के संघों के प्रतिनिधि और उद्योग संघों के प्रतिनिधि।
- स्टार्टअप इंडिया: द वे अहेड 'के उद्देश्यों को साकार करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे प्रधानमंत्री ने इस साल जनवरी में लॉन्च किया था। इससे भारत को एक मंच पर पहुंचने में मदद मिलेगी, जहां दुनिया भर के देश भारत की उपलब्धियों के आधार पर अपने स्वयं के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मॉडल तैयार करेंगे और 'स्टार्टअप इंडिया' को ग्लोबल स्टेज पर ले जाएंगे।

ACHIEVERS IAS ACADEMY

3. एम्पावर्ड ग्रुप 2 (ईजी 2)

- सीओवीआईडी के दौरान आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप 2 (ईजी 2) की बैठक आयोजित की गई।
- सक्रिय COVID मामलों के उच्च बोझ वाले 12 राज्यों से चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान । जबकि महाराष्ट्र में मांग राज्य की उपलब्ध उत्पादन क्षमता से परे होने की उम्मीद है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की उनकी मांग को पूरा करने के लिए कोई उत्पादन क्षमता नहीं है। इसके अलावा, अन्य ऑक्सीजन उत्पादक राज्यों जैसे गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आदि में भी मांग बढ़ने का रुझान है।
- अगले कुछ हफ्तों में मामलों में वृद्धि हुई ऑक्सीजन पर राज्यों को स्पष्टता और आश्वासन देने के लिए, DPIIT, MOHFW, इस्पात मंत्रालय, विभिन्न गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा संयुक्त रूप से एक मानचित्रण अभ्यास किया गया था। ऑक्सीजन समूह, ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (AIIGMA) के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ एम्पावर्ड ग्रुप 2 (ईजी 2) के निर्देशों के अनुसार। चिकित्सा ऑक्सीजन के स्रोतों और उनकी उत्पादन क्षमता को राज्यों की आवश्यकता से मिलान करने के लिए मैप किया गया था और चिकित्सा ऑक्सीजन के स्रोतों पर राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक सांकेतिक रूपरेखा विकसित की गई है।
- तदनुसार, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को उनकी अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 4880 मीट्रिक टन, 5619 मीट्रिक टन और 6593 मीट्रिक टन इन 12 राज्यों को संकेत दिया गया है। MOHFW इस संबंध में आदेश जारी कर रहा है और इसे MHA द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
- EG2 ने MOHFW को पीएसए संयंत्रों की स्थापना के लिए मंजूरी के विचार के लिए दूर दराज के अन्य 100 अस्पतालों की पहचान करने का निर्देश दिया।
- 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का आयात: मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती माँग को देखते हुए, ईजी 2 ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात के लिए एक निविदा जारी करने का निर्णय लिया। एमओएचएफडब्ल्यू को उसी के लिए निविदा को अंतिम रूप देने के लिए निर्देशित किया गया है और एमईए के मिशनों द्वारा पहचाने जाने वाले आयात के संभावित स्रोतों का पता लगाने के लिए भी।
- ईजी 2 चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति की स्थिति की निरंतर निगरानी कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चिकित्सा ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति का समर्थन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

4. कोहली विजडन के 2010 के एकदिवसीय खिलाड़ी

- विराट कोहली को विजडन अल्मैक के 2010 के एकदिवसीय खिलाड़ी का नाम दिया गया है, जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को लगातार दूसरे समय के लिए 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' घोषित किया गया था।
- कोहली, जिन्होंने 2008 में एकदिवसीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और 2011 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे, ने 10 साल के खिंचाव में 11,000 से अधिक रन बनाए, 60 से अधिक की औसत और 42 शतक बनाए।
- सचिन तेंदुलकर को 1990 के वनडे क्रिकेट और कपिल देव को 1980 के दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ नामित किया गया था।

5. गगनयान मिशन

- भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए!

ACHIEVERS IAS ACADEMY

- समझौते की घोषणा फ्रांसीसी विदेश मामलों के मंत्री जीन-यवेस ले ड्रियन के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) मुख्यालय की यात्रा के दौरान की गई थी।
- ISRO ने CNES को गगनयान मिशनों की तैयारी में मदद करने और इस डोमेन में अपने एकल यूरोपीय संपर्क के रूप में काम करने के लिए कहा है।
- समझौते की शर्तों के तहत, CNES भारत के फ्लाइट फिजिशियन और CAPCOM मिशन कंट्रोल टीमों को फ्रांस में CADMOS केंद्र में टूलूज़ में CNES और कोलोन में यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री केंद्र (EAC) में माइक्रोग्रैविटी अनुप्रयोगों और अंतरिक्ष संचालन के विकास के लिए प्रशिक्षित करेगा।
- समझौता सीएनईएस के लिए सत्यापन मिशनों पर एक वैज्ञानिक प्रयोग योजना के कार्यान्वयन का समर्थन करने, खाद्य पैकेजिंग और पोषण कार्यक्रम पर सूचना का आदान-प्रदान करने और फ्रांसीसी उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा सभी उपयोग के ऊपर प्रदान करता है।
- CNES द्वारा विकसित फ्रांसीसी उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में परीक्षण किए गए और अभी भी काम कर रहे हैं, इस प्रकार यह भारतीय दल को उपलब्ध कराया जाएगा।
- सीएनईएस भी फ्रांस में बने फायरप्रूफ कैरी बैग की आपूर्ति करेगा ताकि झटके और विकिरण से उपकरण को बचाए जा सके।
- अगस्त 2018 में गगन्यायन कक्षीय अंतरिक्ष यान परियोजना को बंद कर दिया गया था। यह मूल रूप से 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का था।

6. 156 देशों के लिए ई-वीजा

- गृह मंत्रालय ने 156 देशों के विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई-वीजा) सुविधा बहाल की है, जो चिकित्सा परिचारकों के मामले में व्यापार, सम्मेलनों और चिकित्सा कारणों के लिए भारत आने का इरादा रखते हैं। पर्यटकों के लिए ई-वीजा बहाल किया जाना बाकी है।
- यद्यपि यह सुविधा 171 देशों में उपलब्ध है, 2020 में प्रतिबंधों की घोषणा के बाद, इसे केवल 156 देशों के लिए बहाल किया गया है। चीन, यू.के., कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया और सऊदी अरब उल्लेखनीय अपवाद हैं।
- भारत ने पहले 22 अक्टूबर, 2020 को वीजा प्रतिबंधों में ढील दी थी, ताकि विदेश में मिशन और दूतावासों से नियमित वीजा प्राप्त करने के बाद विदेशियों को व्यापार, सम्मेलन, रोजगार, शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भारत आने में सक्षम बनाया जा सके।
- एक ई-वीजा पांच श्रेणियों में प्रदान किया जाता है - पर्यटक, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सा परिचर।
- व्यवस्था के तहत, एक विदेशी यात्रा से चार दिन पहले ऑनलाइन (https://indianvisaonline.gov.in/) आवेदन कर सकता है। विवरण सत्यापित होने के बाद, एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) उत्पन्न होता है, जिसे आव्रजन चेकपोस्ट पर आगमन पर प्रस्तुत करना होता है। ई-वीजा के माध्यम से प्रवेश केवल भारत में 28 नामित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 5 प्रमुख बंदरगाहों पर अनुमति है।

7. UNFPA की जनसंख्या रिपोर्ट 2021

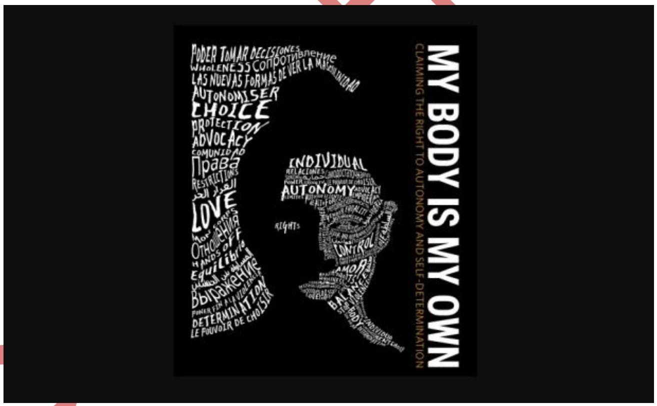

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की प्रमुख राज्य विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 के शीर्षक के अनुसार, 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जिसमें गर्भनिरोधक का उपयोग करना, स्वास्थ्य सेवा की मांग करना या अपनी कामुकता पर भी विचार करना शामिल है। 'माई बॉडी इज माई ओन' को लॉन्च किया गया।
- यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने शारीरिक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे हिंसा के डर के बिना आपके शरीर के बारे में या किसी और के लिए निर्णय लेने की शक्ति और एजेंसी के रूप में परिभाषित किया गया है।
- रिपोर्ट बताती है कि जिन देशों में डेटा उपलब्ध है, वहां केवल 55% महिलाओं को ही स्वास्थ्य सेवा, गर्भनिरोधक और सेक्स के लिए हां या ना कहने की क्षमता पर विकल्प बनाने का पूरा अधिकार है। यह भी रेखांकित करता है कि केवल 75% देश कानूनी रूप से गर्भनिरोधक के लिए पूर्ण और समान पहुंच सुनिश्चित करते हैं।
- शारीरिक स्वायत्तता के उल्लंघन के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं, बाल विवाह, महिला जननांग विकृति, गर्भनिरोधक विकल्पों की कमी, अनियोजित गर्भावस्था के लिए अग्रणी, एक घर और भोजन के लिए अवांछित सेक्स का आदान-प्रदान या जब विभिन्न यौन झुकाव वाले और लिंग पहचान वाले लोग बिना सड़क के नीचे चल सकते हैं। हमले या अपमान का डर। इसके दायरे में विकलांग लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार, हिंसा से मुक्त होने और सुरक्षित और संतोषजनक यौन जीवन का आनंद लेने के लिए भी आते हैं।
- दुनिया भर में महिलाओं को इस स्थिति को और अधिक बढ़ाने के साथ COVID-19 महामारी के साथ शारीरिक स्वायत्तता के मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है... गर्भनिरोधक, रोके जा सकने वाली मातृ मृत्यु, लिंग के लिए वैश्विक

एकजुटता को समाप्त करने के UNFPA के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शारीरिक स्वायत्तता को प्राप्त करना आवश्यक है।

- भारत में, NFHS-4 (2015-2016) के अनुसार, वर्तमान में केवल 12% विवाहित महिलाएं (15-49 वर्ष की आयु) स्वतंत्र रूप से अपनी स्वास्थ्य सेवा के बारे में निर्णय लेती हैं, जबकि 63% अपने जीवनसाथी के परामर्श से निर्णय लेते हैं। एक चौथाई महिलाओं (23%) के लिए, यह जीवनसाथी है जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय लेता है। वर्तमान में विवाहित महिलाओं में से केवल 8% (15-49 वर्ष) स्वतंत्र रूप से गर्भनिरोधक के उपयोग पर निर्णय लेती हैं, जबकि 83% अपने पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं। गर्भनिरोधक के उपयोग के बारे में महिलाओं को प्रदान की गई जानकारी भी सीमित है - गर्भनिरोधक का उपयोग करने वाली केवल 47% महिलाओं को विधि के दुष्प्रभावों के बारे में सूचित किया गया था, और 54% महिलाओं को अन्य गर्भ निरोधकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी।
- शारीरिक स्वायत्तता के लिए महिलाओं की पहुंच को उनकी प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, गर्भनिरोधक उपयोग और यौन संबंधों के बारे में अपने स्वयं के निर्णय लेने की शक्ति के माध्यम से रिपोर्ट में मापा जाता है और इन फैसलों को करने के लिए किसी महिला के अधिकार के साथ देशों के कानून समर्थन या हस्तक्षेप करते हैं।

8. एनपीएस ग्राहकों के लिए वार्षिकी खंड

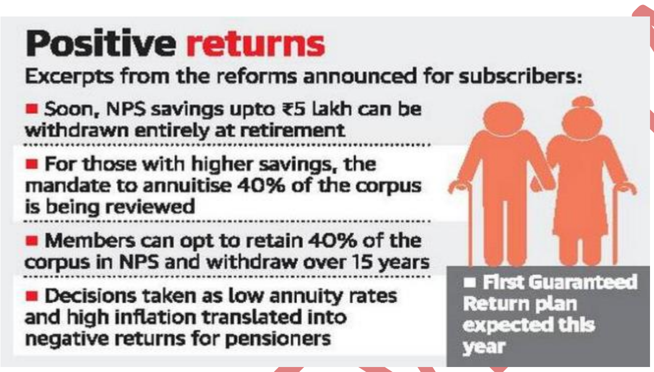

- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अब निवेशकों को अपनी संचित सेवानिवृत्ति कॉर्पस के 40% को वार्षिकी में बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि वार्षिक आय और उच्च मुद्रास्फीति पर खराब पैदावार नकारात्मक रिटर्न में तब्दील हो रही है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अध्यक्ष , सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा।
- नियामक नए नियमों को जल्द ही जारी करेगा, जो रुपये तक की बचत कर सकते हैं। 5 लाख रुपये एनपीएस में, सेवानिवृत्ति पर पूरी राशि लेने के लिए, रुपये से। वर्तमान में 2 लाख। पेंशन फंड नियामक आने वाले वर्ष में पहली गारंटीकृत रिटर्न एनपीएस योजना शुरू करने की उम्मीद कर रहा है।
- अनुमति देने के लिए 2013 के PFRDA अधिनियम में अलग से संशोधन किए जाएंगे!NPS सदस्यों का 5 लाख से अधिक शेष राशि NPS में कॉर्पस का 40% बनाए रखने के लिए या एक व्यवस्थित निकासी योजना के लिए एक प्रणाली के माध्यम से वर्षों में इसे संशोधन किया जाएगा।
- सेवानिवृत्ति के बाद, एक व्यक्ति को कानून के जनादेश के अनुसार कुल धन का 40% वार्षिक के रूप में लेना पड़ता है, और 60% एकमुश्त के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन वार्षिकी दर हमेशा बाजार में ब्याज दरों को ट्रैक करते हैं जो बहुत कम हो गए हैं।
- वित्त मंत्रालय ने बजट 2019-20 के बाद से PFRDA कानून में संशोधन करने और वैधानिक वार्षिकीकरण प्रावधान को ओवरराइड करने के लिए विधायी परिवर्तन करने की योजना की घोषणा की है।

9. जनगोष्ठी समन्वय परिषद, असम (JSPA)

- जनगोष्ठी समन्य परिषद, असम (JSPA) ने असम के मुस्लिमों को उनके प्रवासी, बंगाल मूल या बंगाली भाषी समकक्षों से अलग करने की पहली जनगणना करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया।
- JSPA असमिया मुसलमानों की तीन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है - गोरिया जो विभिन्न स्वदेशी समूहों और जनजातियों से परिवर्तित हुए, मोरिया जिनके पूर्वज अहोम राजाओं द्वारा हथियार और बर्तन बनाने के लिए लाए गए थे और देसी जो विशेष रूप से कोच-राजबंशी समुदाय से परिवर्तित हुए थे।
- तीन महीने के अभ्यास, जिसे नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) के एक छोटे पैमाने के संस्करण के रूप में देखा जाता है, 1800 के दशक की शुरुआत में असम के ब्रिटिश एनेक्सेशन के अनुरूप कट-ऑफ अवधि है। JSPA असम के पूर्व-ब्रिटिश शासन के मुसलमानों को स्वदेशी मानता है, यही कारण है कि जोलाहास - चाय बागान श्रमिकों में से एक है, जो ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा मध्य भारत से लाए गए थे - को जनगणना से बाहर रखा गया है।
- अगस्त 2019 में जारी, NRC ने भारत के नागरिकों के रूप में उन्हें स्थापित करने वाले दस्तावेजों की कमी के लिए 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख को बाहर कर दिया था। NRC के लिए कट-ऑफ अवधि 24 मार्च 1971 थी, जैसा कि 1985 के असम समझौते द्वारा विदेशियों का पता लगाने और निर्वासित करने के लिए या "अवैध अप्रवासियों" के लिए निर्धारित किया गया था।
- जेएसपीए के मुख्य संयोजक सैयद मोमिनुल अवल ने कहा, "हमने 15 अप्रैल को असमिया नव वर्ष के साथ मेल खाने और 2021 के अंत तक अभ्यास पूरा करने की उम्मीद करते हुए पोर्टल jspacanim.com पोर्टल लॉन्च किया।"
- यह पोर्टल जेएसपीए के साथ मान्यता प्राप्त या सूचीबद्ध 17 संगठनों और उनके फोन नंबरों को ऑनलाइन पंजीकरण के साथ किसी भी मुद्दे के लिए संपर्क करने के लिए सूचीबद्ध करता है। इन संगठनों में देसी जनगोस्तियो मंच, असम, एक्सोमिया मुस्लिम कल्याण परिषद, खिलोनजीया एक्सोमिया मुसोलमन उन्नायन परिषद और होदो खिलोनजीया मुस्लिम ओइक्यो मंच शामिल हैं।
- “यह अभ्यास आवश्यक था क्योंकि कुछ प्रवासी मुसलमानों ने असम में रहने वाले सभी मुसलमानों को एक छतरी के नीचे लाने की पहल की है। हमारा धर्म

और नाम एक ही हो सकता है लेकिन स्वदेशी मुसलमानों की एक अलग पहचान है, जो अहोम और कोच राजाओं द्वारा दी गई है!

- 2011 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिमों की आबादी असम की 34.22% है। जेएसपीए का दावा है कि असम में आज लगभग 1.4 करोड़ मुस्लिम हैं, जिनमें से 40 लाख स्वदेशी मुसलमान हैं।

10. Eatsmart सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज लॉन्च किया गया!

- श्री हरदीप एस पुरी, एमओएस (आई / सी), हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चॅलेंजेट को एक ऑनलाइन इवेंट में लॉन्च किया।
- ईटस्मार्ट सिटीज़ चैलेंज का उद्देश्य स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना है जो संस्थागत, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे द्वारा समर्थित एक स्वस्थ, सुरक्षित और स्थायी खाद्य वातावरण का समर्थन करती है और साथ ही भोजन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए 'स्मार्ट' समाधानों के आवेदन के साथ। Transport4All डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल समाधान विकसित करने के लिए चुनौती देता है जो सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, सस्ती, आरामदायक और सभी के लिए विश्वसनीय बनाएगा।
- ट्रांसपोर्ट 4 ऑल (T4All) चैलेंज
- भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन में निवेश करने के लिए एक सामाजिक अच्छा, पूरी तरह से अनौपचारिक पारगमन सेवाओं को फिर से शुरू करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल नवाचार को प्राथमिकता देने का सुनहरा अवसर है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ITDP के सहयोग से परिवहन 4 सभी चुनौती का शुभारंभ किया। इस चुनौती का उद्देश्य शहरों, नागरिक समूहों और स्टार्ट-अप को एक साथ समाधान प्रदान करना है जो सभी नागरिकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार करते हैं।
- चैलेंज के मूल में वे नागरिक हैं जो न केवल उन समस्याओं को परिभाषित करेंगे जिनके लिए समाधान तैयार किए जाएंगे बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाधानों को निखारने के लिए स्टार्ट-अप्स और शहरों की मदद भी करेंगे। चैलेंज का पहला संस्करण डिजिटल नवाचार पर केंद्रित है। शहरों और स्टार्ट-अप को विभिन्न समाधानों को विकसित करने और परीक्षण करने, उनसे सीखने और सार्वजनिक परिवहन में लोगों का विश्वास बनाने और उनकी गतिशीलता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। समाधान सार्वजनिक परिवहन को औपचारिक बनाने के साथ-साथ अनौपचारिक- सुरक्षित, सुविधाजनक और सभी के लिए सस्ती भी बनाएंगे। सभी स्मार्ट सिटीज मिशन शहरों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की राजधानियों, और 5 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों-चुनौती के लिए पात्र हैं।

चैलेंज के तीन चरण

डिजिटल इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से Transport4All में तीन चरण शामिल हैं:

- चरण I समस्या पहचान: शहर, गैर सरकारी संगठनों के समर्थन से, नागरिकों और सार्वजनिक परिवहन के सामने आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान करते हैं

- चरण II समाधान उत्पत्ति: शहरों और गैर सरकारी संगठनों से इनपुट के साथ सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट-अप समाधान के प्रोटोटाइप विकसित करता है

- चरण III पायलट परीक्षण: शहर बड़े पैमाने पर पायलटों के लिए स्टार्ट-अप संलग्न करते हैं और नागरिक प्रतिक्रिया के आधार पर समाधान को परिष्कृत करते हैं

ACHIEVERS IAS ACADEMY